SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Madam, we are also equally important.

SHRIMATI KAMLA SINHA (Bihar): The Attorney-General should be called in this House to give his statement on this issue. We also support it.

SHRI V. GOPALSAMY: This House is also very important. *(Interruptions)*.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदया, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वोटिंग हो चुका है, फिर भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम-कोर्ट में जाकर उस पर स्टे लाया है। यह बहुत गंभीर बात है और डेमोक्रेसी को खतरा है। जैसी मान्यवर मेरे मित्र गौतम जी ने बात उठाई है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ कि अटोर्नी जनरल इस सदन में भी आकर पूरी तरह से हमको जानकारी दें। . . . .**(व्यवधान)** . . .

उपसभापति: ठीक है, आपने जो बात कही, यह बात मैं चेयरमेन साहब तक पहुँचा दूंगी।

because it is entirely up to the Chairman to ask the Attorney-General to address this House also and apprise the Members as to what it is.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Madam, you are competent enough to take a decision. *(Interruptions)*.

SHRI V. GOPALSAMY: We request you to convey our feelings.

श्री संघप्रिय गौतम: आप स्वयं सक्षम हैं, मैडम।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: महोदया, इस सदन का अपमान नहीं होना चाहिए, इस सदन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। . . . . .**(व्यवधान)** . . .

उपसभापति: हर जगह सरकार नहीं करती है। . . . .

Every time it is not for the Government to act. It is not a question of the Government calling the Attorney-General before the House. It is the House that calls the Attorney-General. Government does not call the Attorney-General. Your sentiments will be conveyed to the Chairman. We will do the needful. *(Interuptions)*. All right. I cannot take a decision just now. *(Interruptions)*. The needful will be done. I cannot telephone from here and call everybody. I can call you to sit down.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): You can take the sense of the House.

SHRI G. G. SWELL (Meghalaya): The House is unanimous in the demand that the Attorney-General should appear here also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your sentiments, your desire, your wishes have been registered very well. The needful will be done.

बलराम जी आप कुछ कह रहे थे।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

PREVAILING DROUGHT CONDITIONS IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY

श्री बलराम जाखड़: मैडम, मैं एक दरख्वास्त करना चाहता था आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से कि जिस तरीके की चिंता व्यक्त की जा रही है और स्वाभाविक है होना, मैं चाहूँगा कि जो जो माननीय सदस्यगण इस विषय में विचार व्यक्त करें वह कृपया जरा पूरे टाइम बैठे। आमतौर पर बाद में कोई नहीं होता सुनने के लिए। . . . .**(व्यवधान)** . . . .

मैंने कल भी देखा, परसों भी देखा कि 30-35 सदस्य बोलते हैं और सुनने वाले पांच होते हैं। ऐसे मज़ा ही नहीं आता, न तो बात करने का और न उसका निष्कर्ष निकलता है। कच्ची बात करने की आवश्यकता नहीं है।

It is too much painful for me. I can't.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, Deputy Chairman, I would like to assure the Minister that we are very anxious to hear him on this important subject.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I also share the sentiments of the hon. Minister. But he should apply the same yardstick to their side also.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He had mentioned about all the Members. There is no this side or that side.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Don't make false allegations. . . . *(Interruptions)*. . . .

श्री बलराम जाखड़: गौतम जी बंटवारा करने पर तुले रहते हैं। मैंने तो सबके लिए बोला है।

उपसभापति: समस्या गंभीर है। लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं और आप लोगों ने जो यहां पर मशविरे दिए हैं, मंत्री जी उसका क्या समाधान बताते हैं, क्या करने वाले हैं,

सुनेंगे तो फायदा होगा आईंदा के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए । श्री लहलुवालिया ।

श्री चिमन भाई मेहता (गुजरात) : जो बोलने वाले थे, अगर वे कंसर्न इतना बताते हैं इधर बोलने में तो उसको हाजिर रहना चाहिए । अगर हाजिर नहीं रह सकते, कोई सीरियस हंगेजमेंट है तो आपकी कम से कम परमिशन तो लेनी चाहिए ।

उपसभापति : ठीक मशिवरा है आपका ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार) : महोदया, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जिसकी विडम्बना ही दूसरी है । एक तरफ साउथ बिहार में सूखा पड़ता है तो नार्थ बिहार में बाढ़ की बुरी अवस्था से त्रस्त रहते हैं वहां के लोग । हमारे यहां सूखा आम पड़ता है, पर आज तक मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वह जो ड्राउट प्रोन एरिया है, आइडेंटिफाई करने के बावजूद इन इलाकों पर प्रोग्राम क्यों नहीं लिया जाता? महोदया, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बाढ़ आई हो, वहां की जो तकलीफें हैं, उन पर भाषण देकर अपने आंसू तो हम बहा सकते हैं या उनकी दारिद्रिक अवस्था का चित्रण तो हम बड़े अच्छे कलात्मक ढंग से कर सकते हैं, लोगों को भावनात्मक बना सकते हैं, उनको रूला सकते हैं, पर आखिर हम कर क्या रहे हैं? उसके लिए हम क्या रास्ता अपनाते हैं कि आईंदा हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को ऐसी अवस्थाओं से गुजरना न पड़े? साइंस ने बहुत तरक्की की है । मंत्री महोदय अपनी स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि पहला पैराग्राफ वही था जो फ्लड के टाइम पर पढ़ा, वही मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन । हम निर्भर हैं मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन पर और यह तीन महीने पहले हो जाती, अगर तीन महीने पहले हो जाती तो हम अपना एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहां ज्यादा वृष्टि होने वाली है और कहां कम वृष्टि होने वाली है । जब हम ज्यादा वृष्टि होने वाले इलाकों के लिए अपनी सारी व्यवस्था कर लेते हैं, उसी तरह कम वृष्टि होने वाले इलाकों के लिए भी व्यवस्था हमें करनी चाहिए । पर दुर्भाग्य ऐसा है, महोदया, मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूं । पटना में एक बार 1983 में एक ऐसा मौजू बन गया कि शायद पटना शहर में बाढ़ आ जाएगी । पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ता गया और लोग अपने घरों में तैयारियां करने लगे, तरह-तरह की तैयारियां करने लगे । मेरे परिवार के सदस्यों ने कहा कि आप भी कुछ बंदोबस्त कर लो, घर में कुछ खाने का सूखा सामान लाकर रखो, कल को बाढ़ आ गई और पटना शहर डूब गया तो क्या करोगे? मैं गंगा नदी के किनारे देखने के लिए गया कि क्या मौजू बन रहा है और कैसे पानी बढ़ रहा है । वहां मेरी मुलाकात पटना शहर के सबसे बड़े जौहरी से हुई । मैं उन्हें जानता था क्योंकि उनके बच्चे और मेरे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे । मैंने पूछा कि साहब आप क्या यहां क्या कर रहे हैं । बोले, साहब, मैं तो गंगा मैया की आराधना करने आया हूं कि पानी और चढ़ जाए । मैंने कहा, भइया क्यों? वे बोले कि जितने लोगों के पास काला धन है और रुपए गाड़कर रखे हैं वह रुपए निकालकर सोना खरीद लेंगे और सोना गाड़ देंगे । मैं इसीलिए यहां पर आया हूं । मैंने इतने में देखा कि वहां पर जो कलेक्ट्रेट के नाज़िर हैं, वह भी बैठे हैं । वहां घाट पर जो मंदिर है तथा जो डूब चुका है, वहां वह नाव से जाकर उस मंदिर में आराधना कर रहे हैं । पूछा कि क्या बात है, आप क्या कर रहे हैं? बोले कि साहब, जो रिलीफ बंटेगी उसमें हमारा कुछ खजाना बनेगा । तो हर आदमी अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है । पूरी मशीनरी इस स्वार्थ पर जुड़ी हुई है । हर एक आदमी अपना स्वार्थ ढूंढ रहा है । चाहे सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आए, लोग पैसा बनाने के चक्कर में रहते हैं । लेकिन सरकार का अपना फर्ज है, अपना धर्म है और जब हम यहां लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज है । मुझे देखकर आश्चर्य होता है . . . .**(व्यवधान)**

श्री संघप्रिय गौतम : अगर आप उस धर्म को राजनीति से अलग मत करना ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : अच्छा, आप चुपचाप बैठो । यह डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम हैं । यह ड्रोट प्रोन एरिया की जो रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट में 615 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां डी० पी० ए० पी० प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है । महोदया, पूरे देश में 615 ब्लॉक आईडेंटिफाई किए गए हैं जो 92 डिस्ट्रिक्ट के हैं और 13 राज्यों के हैं । परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि उसमें अगर मैं गिनती करने लगूं तो 309 ब्लॉक हमारे बिहार राज्य के हैं और 44 डिस्ट्रिक्ट हैं । परन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि डी० पी० ए० पी० का प्रोग्राम वहां पहुंचता नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी-ऐसी कंडीशंस लगाई गई हैं । आप क्लेमिटी फंड का पैसा तो देते हैं और पैसा देने के साथ कहते हैं कि 25 प्रतिशत आप दो । अब एक गरीब राज्य कहां से 25 प्रतिशत लाएगा । जब हम अपनी रायल्टी की बात करते हैं, जब हम कोयले की रायल्टी मांगते हैं, तो उसके मिलने पर ही हम 25 प्रतिशत देने के लिए राजी हैं । हमारा बिहार राज्य 25 प्रतिशत देगा । किन्तु हमारी जितनी कोयले की रायल्टी पड़ी है वह हमें दे दी जाए । बॉक्साईट की रायल्टी पड़ी हुई है, वह हमें दे दी जाए । डोलोमाईट, लाईम स्टोन और आयरन की जो रायल्टी है, उसका पूरा पैसा मिले, पूरा हक मिले, ताकि क्लेमिटी फंड में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है हम पूरा कर सकेंगे । परन्तु कंट्रीब्यूशन हम तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हमें रायल्टी का पैसा नहीं मिलता जब तक हमारे पुराने पैसे क्लीअर नहीं होते । तो आखिर हमारे स्टेट की जो रेवेन्यू, अर्निंग है, वह कहां से आएगी । तो ऐसे कुछ लकूने हैं जहां ऐसी-ऐसी कंडीशंस लगाई जाती हैं । परन्तु उस वक्त तक ऐसी कंडीशंस पर रिलिड नहीं होना चाहिए जब वाकई राज्य की जनता बाढ़ से ग्रसित होकर या सूखे से ग्रसित होकर भूखी मर रही हो ।

महोदया, अक्तूबर, 92 में मांग आई थी कि बिहार राज्य ने 1

हजार 117 करोड़ रुपए मांगा था सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए । प्रधान मंत्री जी के वहां जाने पर बिहार राज्य को सिर्फ 180 करोड़ रुपए मिले । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बिहार राज्य को अब तक पहली जुलाई, 93 तक जवाहर रोजगार योजना का क्या एमाउंट उपलब्ध है? क्लेमिटी फंड में आज तक कितना पैसा बिहरार को दिया है ? आपने एक्सलिरेटेड रूरल वाटर सपलाई प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा दिया है? उस इलाके में कितना फूड ग्रेन उपलब्ध है? जब प्रधान मंत्री जी फ्लामू गए थे, वहां हमारे राज्य की जो मांग1 हजार 117 करोड़ रुपए की थी और जहां सिर्फ 180 करोड़ रुपए दिए गए, उससे एडिशनल कोई रुपया प्रधान मंत्री महोदय ने बिहार राज्य को दिया है या नहीं दिया है? महोदया, हम लोग विज्ञान और तकनीकी के बारे में आगे बहुत बढ़चढ़कर कहते हैं कि हमारी उपलब्धियां इतनी-इतनी हो चुकी हैं, पर विदेशों में देखा जाता है कि वहां हाई फार्मिंग के लिए भी तैयारी है ।

आपको जब पता है कि ड्राऊट एरिया आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है, वहां हाई फार्मिंग करने के लिए आपके विज्ञान और टेक्नोलोजी विभाग ने क्या नए बीज उपलब्ध कराए हैं जिससे ऐसे इलाके में फार्मिंग की जा सके क्योंकि देखा गया है कि लोगों ने तो डेजर्ट पर भी कुछ न कुछ ऐसे फल-फूल, पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं और ऐसे बीज उपलब्ध हैं । बॉयोटेक्नोलोजी के माध्यम से नए बीज उपलब्ध हो रहे हैं जिनसे सूखे में भी फार्मिंग की जा सकती है । क्या यह जो ड्राऊट प्रोन ऐरिया है, यहां के लिए भी ऐसे बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और हमारे बिहार में आपने जो 309 ब्लाक हैं, वहां पर आपने अब तक अपने स्पेशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है, यह बताने की कृपा कीजिए ।

महोदया, जहां सूखा पड़े या बाढ़ आए, वहां की बात करते समय हम मूक प्राणियों की बात भूल जाते हैं जो अपनी बात नहीं कह सकते । वह है हमारे पालतू जानवर, जो उसी तरह मरते हैं जैसे मानव मरता है, मनुष्य मरता है । जहां पर सूखा पड़ता है, दुधारू गाय सूख जाती है और मनुष्य तो कहीं भागकर चला जाता है, कोई उपाय ढूंढ लेता है, किसी रोजगार योजना में काम करके अपने लिए अन्न जुटा लेता है पर हमारे जानवर-गाय, भैंस, बकरी जो हमारे किसानों के साथी हैं और हमारे गांवों की उपज के साथी हैं और हमारे गांवों की आर्थिक अवस्था के साथी हैं, उनको बचाने के लिए आपकी कोशिश क्या है?

हमने बहुत सुना कि ड्राऊट एरिया में फौडर उपलब्ध कराने के लिए नए रास्ते अपनाए जाएंगे. उसके बारे में क्या सोचा गया है । मैं यहां पर अपने राज्य के मुख्य मंत्री लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने चरवाहा स्कूल शिक्षा प्रणाली का रास्ता अपनाया । उनके दिमाग में यह भी था कि चरागाह बनाए जाएं और चरागाह बनाने के लिए केंद्रीय सरकार कितनी मदद करेगी क्योंकि फौडर प्लानिंग के बारे में राजीव गांधी के समय में बहुत कुछ किया गया और बहुत सारे उपक्रम लाए गए । उस समय गुजरात में जबरदस्त सूखा पड़ा और वहां की गाय-भैंसों को बचाने के लिए जबरदस्त प्लानिंग की गई थी । हमारे राज्य के जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, वहां पर चारा उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय केन्द्रीय सरकार कर रही है और इसके लिए वह क्या सहायता देगी, मैं यह जानना चाहता हूं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बिहार को कितना पैसा दिया है और हमारी जो टोटल डिमांड है 1117 करोड़ रुपए की, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं क्योंकि यह हमारी बहुत बड़ी विडंबना है कि आधा बिहार सूखे से ग्रस्त रहता है और आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त रहता है । वही अवस्था हमारी भी है । एक रात की यात्रा करने पर आप बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंच जाते हैं और उसके आगे 12 घंटे के रास्ते पर आप सूखाग्रस्त इलाके में पहुंच जाते हैं । आप जरा इस ओर गंभीरता से ध्यान दीजिए । इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । धन्यवाद ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर : माननीय उपसभापति महोदया, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं । माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाए हैं, कृषि मंत्री महोदय चाहते हैं कि मैं उनका उत्तर दूं ।

उपसभापति : एक मिनट है । ठीक है, आप बोल दीजिए ।

श्री रामेश्वर ठाकुर: जहां तक जवाहर रोजगार योजना का सवाल है, बिहार में इस साल एक अप्रैल को 43 करोड़ रुपए उनके पास थे । हमने पिछले साल के मुकाबले अतिरिक्त राशि के रूप में 83 करोड़ रुपए दिए और इस साल हमने 87 करोड़ रुपए दिए हैं । इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल, 1993 को फ्लामू गए थे । उस समय बिहार राज्य के लिए सुखाड़ से निपटने के लिए 175 करोड़ रुपए दिए गए । इस प्रकार कुल मिलाकर 463 करोड़ रुपए राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए । तीस जून, 1993 तक जो सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई है उसके मुताबिक 78 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए और एक जुलाई को 384 करोड़ रुपए उनके पास मौजूद हैं ।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal) : Is it intervention ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : No; he is only giving information. Because we had one minute. I said he can give.

लंबा है क्या आपका भाषण ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : मध्य प्रदेश के लिए पूछा गया है । कुल मिलाकर 309 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिसमें से 75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और 234 करोड़ रुपए एक जुलाई, 1993 को उनके पास मौजूद थे ।

उपसभापति : मंत्री जी, आप खाली बिहार का दे रहे हैं । What about Andhra ? What about Karnataka and Maharashtra ? It is discrimination against other States.

श्री रामेश्वर ठाकुर : ये आंकड़े मैं मध्य प्रदेश के दे रहा हूं ।

उपसभापति : फिर आप बाद में बोल दीजिएगा । अभी लंच हो जाएगा ...**(व्यवधान)**.....

What about Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Maharashtra ?

SHRI SARADA MOHANTY : And what about Orissa, Madam ?...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is only about Bihar. .....*(Interruptions)*... I would request the Hon. Minister to give completely all the figures for all the States so that the States which have got a drought would have an idea of what is happening for their States. I know you are from Bihar. You have got better information about it. The House is adjourned for lunch till 2.30 P. M.

The House then adjourned for lunch at thirty two minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, **The Vice-Chairman Shri MD. Salim** in the Chair.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Prevailing drought conditions in different parts of the country—Contd.

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस देश की एक बड़ी विडंबना है कि देश के बहुत बड़े हिस्से, पूर्व, उत्तर और पश्चिम, सब तरफ बाढ़ का प्रकोप रहा । पिछले दिनों में इसी सदन में बाढ़ के ऊपर बड़ी गंभीरतापूर्वक चर्चा की । लेकिन यह भी विडंबना है कि आज देश के बहुत से राज्यों के अनेक जिलों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । अभी मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि अनेक स्टेट्स में सूखा पड़ा हुआ है, जिसमें बिहार भी है, कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है । लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान विशेषतौर से उत्तर प्रदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश का जिक्र तो किया है लेकिन बहुत थोड़ा-सा किया है । मालूम पड़ता है कि अधिकारी-वर्ग ने माननीय मंत्री जी को उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की पूरी रिपोर्ट—जो सारे जिलों की स्थिति है उनकी सूखे के संबंध में पूरी रिपोर्ट आन दि स्पाट जाकर नहीं दी है । मेरे ख्याल से ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि वहां पर राज्यपाल महोदय का शासन है और अधिकारी वर्ग को इसमें जो दिलचस्पी लेनी चाहिये थी, उसने यह दिलचस्पी नहीं ली । मान्यवर, मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 42 जिलों की अनेक तहसिलों में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है । इलाहाबाद का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है लेकिन उसके अलावा आजमगढ़ है, बनारस है, मऊ है, मिर्जापुर है । ये सब जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं । वहां पर आदमियों को पीने के लिये पानी नहीं मिल पा रहा है, भोजन नहीं मिल पा रहा है । साथ ही साथ वहां जो पशु हैं उनको चारा नहीं मिल पा रहा है । यह स्थिति जो है यह उत्तर प्रदेश की है । लगता है कि कहीं कम्युनिकेशन गैप है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है उसकी सही जानकारी केंद्रीय सरकार को नहीं मिल पायी है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सूखे की जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वह उसकी जानकारी सदन को दे दें । जैसा कहा गया कि वहां पर भयंकर सूखा है वैसे ही यह भी सही है और जैसा आप देखते हैं कि प्रकृति का एक नियम है कि हर तीसरे साल देश में सूखा पड़ता है । जैसे सूखा टलता नहीं है वैसे ही बाढ़ का प्रकोप भी भयंकर रहता है । यह प्रकृति का नियम है कि सूखा भी पड़ता है और हर साल बाढ़ भी आती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो परमानेंट फीचर है, बाढ़ और सूखा, इसके लिये बाकायदा वार फुटिंग पर हमको काम करना चाहिये । हमको यह तय कर लेना चाहिये कि कौन-सी स्टेट में, कौन से जिलों के किन हिस्सों में, किन इलाकों में सूखा पड़ता है, वहां पर इमीडिपेटली रिलीफ का काम किस तरह से हो सकता है । दूरदराज इलाकों में जो काम पहले से करना चाहिये उसे कर दिया जाना चाहिये । होता यह है कि जब सूखा पड़ता है तो फिर दौड़ते हैं । मुझे खुशी है कि हमारे मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि बहुत सारा रुपया दिया गया । उसे 180 करोड़ रुपया मिला और बिहार को तो 330 करोड़ रुपया मिला । अभी माननीय ठाकुर साहब ने बताया कि बिहार को इतने सारे रुपये दिये गये । तो मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार इस मायने में बड़ी जागरूक, चेतन रही । इस समस्या का उसको आभास था इसलिये फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं हुई । प्रधानमंत्री जी ने खुद सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ित इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया । हमारे कृषि मंत्री जी ने भी दौरा किया । तो केंद्र सरकार का यह रोल नहीं रहा है कि वह प्राकृतिक मर्सी पर लोगों को छोड़कर बैठी रही । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखा होने के बावजूद भूख के कारण लोगों की जान जो प्राय: बड़े पैमाने पर जाती है, वह नहीं हो पाया । हमारी मिलेट्री के नौजवानों ने बाढ़ में काम किया, सेना के लोगों ने काम किया, पुलिसवालों ने काम किया है, वालेंटरी आर्गनाइजेशन ने काम किया । इस बार जो भयंकर बाढ़ आयी, सरकार की सूझबूझ, दूरदर्शी का नतीजा है कि इससे जितना नुकसान होना चाहिये था, जितना नुकसान हमें लग रहा था, वह नहीं हुआ, बहुत कम नुकसान हुआ । इसके लिये हमारी केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है जो उसने इस सारी बिगड़ती अवस्था को, इस भयंकर